

# 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी: औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने की समीक्षा; भूखंड आवंटन में तेजी और भूमि सुधारों पर जोर

## 3 लाख नए रोजगार सृजित, फैक्ट्री पंजीकरण में 33% की रिकॉर्ड वृद्धि

लखनऊ (विधान केसरी)। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को गति देने के लिए राज्य सरकार ने अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। गुरुवार को इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में निवेशकों को आसानी से भूमि उपलब्ध कराने, सिंगल विंडो सिस्टम और औद्योगिक भूमि बैंक के विस्तार पर विशेष चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों ने 15,610 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है, जो पिछले तीन वर्षों में 133 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। इसमें से 2,671 एकड़ भूमि का आवंटन औद्योगिक उपयोग के लिए किया जा चुका है। मंत्री नन्दी ने निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में निरस्त किए गए भूखंडों की अद्यतन रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत की जाए और

आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी व त्वरित बनाया जाए। इसके साथ ही बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बिडा) को राज्य के पहले विनिर्माण क्षेत्र के रूप में तेजी से विकसित करने पर जोर दिया गया। नई फैक्ट्रियों का पंजीकरण: वित्तीय वर्ष 2025-26 में फैक्ट्री अधिनियम के तहत 4,860 नई इकाइयों का पंजीकरण हुआ (33% की वृद्धि)। रोजगार सृजन: 3 लाख से अधिक युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिले। निर्यात में उछाल: राज्य का कुल निर्यात 2.01 लाख करोड़ के स्तर तक पहुंच गया है। बैठक में

500 करोड़ से अधिक के बड़े प्रोजेक्ट्स पर विशेष ध्यान अपर मुख्य सचिव (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) आलोक कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने निर्देश दिए कि 500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) और वित्तीय सेवा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के लिए चिन्हित परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए हैं।

### 'निवेश मित्र 3.0' से आसान होगा व्यापार

इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने बताया कि प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए 'निवेश मित्र 3.0' की शुरुआत की गई है। इसके तहत पर्यावरणीय स्वीकृतियों और भवन उपविधियों के अनुमोदन में निजी एजेंसियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुगम होंगी। जल्द ही प्रदेश में टेक्सटाइल, लेदर और जीसीसी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित 'क्षेत्र-विशिष्ट निवेश सम्मेलन' आयोजित किए जाएंगे।

राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद सहित वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी सेल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।